चाईबासा

dainikbhaskar.com

दैनिक भास्कर, जमशेदपुर, शुक्रवार, 14 जनवरी, 2016

केयू | विश्वविद्यालय व कॉलेजों को डाटा अपलोड करने का मिला प्रशिक्षण

डाटा अपलोड किए बिना नहीं मिलेगा कोई भी ग्रांट

भास्कर न्यूज | चाईबासा

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के डाटा अपलोड कराने की जानकारी देने के लिए बुधवार को कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण के लिए रांची से रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) के नोडल पदाधिकारी डॉ. शंभू नारायण सिंह व सुनीत आनंद के द्वारा किस तरह से डाटा अपलोड कराया जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। स्पष्ट रूप से कॉलेजों से आए प्रोफेसर इंचार्ज व प्रतिनिधियों को बताया गया कि डाटा को सही तरीके से अपलोड नहीं करने पर कॉलेज व विश्वविद्यालय को केन्द्र व राज्य सरकार से किसी तरह का ग्रांट नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में कॉलेज व विश्वविद्यालय के संचालन के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वहीं छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि पर भी रोक लग जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉलेज व विवि को सत्र 2014-15 के सभी डाटा तीन से चार दिनों में अपलोड कराने के लिए कहा गया। वहीं सत्र 2015-16 के लिए फरवरी माह के अंत तक इसे हर हाल में अपलोड करा लेने की सलाह दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में कोल्हान विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत व स्थायी संबद्धता प्राप्त कॉलेजों के प्रचार्यों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में केयू की डीएसडब्लू डा. पद्मजा सेन, कुलसचिव डा. एसएस दास आदि भी मौजूद रहे।

कोल्हान विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित कार्यशाला में जानकारी देते रूसा के नोडल पदाधिकारी।

डाटा में ये देनी होगी जानकारी

विश्वविद्यालय व कॉलेजों में कितने शिक्षक कार्यरत हैं, कितने शिक्षकेतर कर्मी हैं, छात्रों की संख्या कितनी है, कितनी छात्राएं नामांकित हैं, एससी, एसटी व ओबीसी व सामान्य श्रेणी के कितने विद्यार्थी हैं। कॉलेजों व विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के संचालन के लिए किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। छात्रावास की सुविधा, शौचालय, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी आदि की किस तरह की सुविधा है। कितने शिक्षकों के द्वारा रिसर्च किया जाता है। कितने जर्नल में शिक्षकों के कार्य पेश किए गए हैं आदि का डाटा अपलोड करना होगा।

ये होगी परेशानी

रूसा (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान) व नैक (नेशनल एक्रिडेशन एसेसमेंट काउंसिल) में भी ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के डाटा अपलोड नहीं करने पर समस्या उत्पन्न होगी। इस कारण शिक्षण संस्थानों को कई लाभ से वंचित होना पड़ेगा। एआईएसएचई के पास उपलब्ध कॉलेज व विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड डाटा के आधार पर ही केन्द्र सरकार की हायर एजुकेशन के लिए पॉलिसी तय होगी। डाटा के आधार पर ही कॉलेजों की सुविधा भी तय होगी।

कार्यशाला में उपस्थित विभिन्न कॉलेजों के पदाधिकारी व प्रतिनिधि।

कई कॉलेजों ने नहीं किया डाटा अपलोड

ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के निर्धारित फॉर्मेट में कॉलेजों द्वारा आधा-अधूरा डाटा अपलोड किया गया है। वहीं विवि के कई कॉलेजों में दो वित्तीय वर्ष का डाटा अपलोड नहीं हुआ है। 2013-14 व 2014-15 के लिए जैसी जैन कॉमर्स कॉलेज, चाईबासा कॉलेज जमशेदपुर व एलबीएसएम कॉलेज ने डाटा अपलोड नहीं किया है। वहीं लोयला कॉलेज, जाईट कॉलेज के द्वारा अब तक दो सत्र का डाटा अपलोड नहीं किया गया है। संत अगस्तीन कॉलेज ने तो कोई डाटा अपलोड ही नहीं किया।